आपकी कमी बस आप ही सुधार सकते है।–अज्ञात

विचार-प्रवाह देहरादून, रविवार, 14 नवंबर 2021

पेज थ्री
www.page3news.in

महिलाएं काफी तेजी से आगे बढ़ीं

गौर करने की बात है कि अन्य तमाम क्षेत्रों में तो महिलाएं काफी तेजी से आगे बढ़ी हैं, लेकिन सेना में उनकी गति काफी धीमी रही। करीब 14 लाख सैनिकों वाली आर्मी में आज भी महिलाओं का प्रतिशत 0.56 ही है।

अंजु सिंह।।

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि आर्मी में महिलाओं के साथ भेदभाव करने वाली मानसिकता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अंतरिम आदेश के जरिए कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि आगामी एनडीए (नैशनल डिफेंस अकैडमी) प्रवेश परीक्षा में महिलाएं भी बैठ सकेंगी। हालांकि उनका नामांकन इस मामले में आने वाले अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा, लेकिन कोर्ट के इस फैसले की अहमियत महज एडमिशन प्रॉसेस तक सीमित नहीं है।

कोर्ट का ध्यान मुख्य तौर पर इस बड़े सवाल पर था कि आखिर आर्मी में महिलाओं के सवाल पर खुलापन क्यों नहीं दिख रहा? क्यों हर बार कोर्ट को दखल देकर फैसला सुनाना पड़ता है और फिर भी बात उस खास मामले से जुड़े फैसले पर अमल तक ही सीमित रह जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ती? गौर करने की बात है कि अन्य तमाम क्षेत्रों में तो महिलाएं काफी तेजी से आगे बढ़ी हैं, लेकिन सेना में उनकी गति काफी धीमी रही। करीब 14 लाख सैनिकों वाली आर्मी में आज भी महिलाओं का प्रतिशत 0.56 ही है। इस मामले में पिछले साल फरवरी में आया सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला ऐतिहासिक माना जाता है, जिसमें अदालत ने न केवल महिलाओं को कमांड पोस्टिंग के लायक बताया बल्कि केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया कि उन्हें परमानेंट कमिशन दिया जाए।

ध्यान रहे, उस मामले में महिलाओं को परमानेंट कमिशन न दिए जाने के पक्ष में यह दलील भी दी गई थी कि सेना में ज्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग होते हैं, जिनके लिए महिलाओं से आदेश लेना सहज नहीं है। कोर्ट ने न केवल इस दलील को खारिज किया बल्कि इस मानसिकता को भी बदलने की जरूरत बताई। उसके बाद हालांकि इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन एनडीए परीक्षा में महिलाओं को बैठने से रोकना और उसे नीतिगत मामला बताना स्वीकार्य नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही प्रवेश परीक्षा में महिलाओं को बैठने देने से ज्यादा अहमियत इस सवाल को दी कि आखिर सेना में इस मानसिकता को बदलने के कारगर प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे।

कोर्ट ने फिलहाल खुद को अंतरिम आदेश तक सीमित रखते हुए कहा कि हर मामले में उसके आदेश का इंतजार करना सही नहीं है। सरकार और सेना खुद आवश्यक कदम उठाकर अपनी नीति दुरुस्त करे। हालांकि सेना में लिंग निरपेक्ष नीतियों का मामला उतना सरल नहीं है। महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट और ठहरने की अलग व्यवस्था के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास भी जरूरी है, जो रातोरात नहीं हो सकता। लेकिन महिलाओं को हर फील्ड में समान अवसर देने के संवैधानिक तकाजे को पूरा करने की राह में किसी भी बाधा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उम्मीद की जाए कि अब इस मामले में सेना और सरकार प्रो–ऐक्टिव रोल में नजर आएगी।

थोड़ा भोजन

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। जीवन से पूछा की क्या कर रहे हो जीवन ने कहा की खाना बना रहा हु जीवन श्री राम जी को पहचान भी नहीं पा रहे थे। श्री राम जी ने कहा की क्या तुम थोड़ा भोजन मुझे भी खिला सकते हो जीवन ने कहा की ठीक है जब भोजन बन चुका तो जीवन ने श्री राम जी को भोजन दिया और भोजन करके श्री राम जी बोलो की अगले दिन हम और हमारे भाई भी आएंगे उनके लिए भी भोजन तैयार कर लेना जीवन अब सबका भोजन बना कर ले गया और अगले दिन भोजन के लिए और ज्यादा समान की मांग करने लगा इस पर साधू जी ने सोचा की शायद इसे भूख जयादा लगती होगी और जीवन को जयादा समान दे दिया गया और समान लेकर जीवन नदी के किनारे पर चला गया ।

संपादकीय

बदलता बौद्धिक ढांचां

एक बड़ी चुनौती लोकतंत्र के लिए यह है कि लोकतांत्रिक देश खुले होते हैं। जबकि चीन और रूस को वहां की सरकारें कंट्रोल करती हैं। ये लोग लोकतांत्रिक देशों में सोशल मीडिया पर अफवाहबाजी की कैंपेन चला सकते हैं। चीन और रूस की ये हरकतें युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर रही हैं। पहले सिर्फ हथियारों से लड़े जाने वाले युद्ध से बचना था तो दूसरे के हथियारों से अच्छे हथियार ले आए तो युद्ध की संभावना कम हो जाती थी। लेकिन अब यह कैनवास बड़ा हो चुका है क्योंकि अब सिर्फ बम या बंदूक से ही नहीं बचना है। इसी तरह से बाकी देश भी अलग–अलग तकनीक का इस्तेमाल करके दुश्मन देश को नुकसान पहुंचाते हैं। चाहे वे उसके महत्वपूर्ण ढांचे को टारगेट करें, या फिर करेंसी और अर्थव्यवस्था को, इन सारे संघर्षों में युद्ध जैसे ही हालात बनते हैं। इसमें आपको यह सोचना पड़ता है कि आप कैसे रिएक्ट करें, आपकी पॉलिसी क्या होगी। परंपरागत तरीका बदल रहा है, तकनीक बदल रही है, और अब तो नेशनल सिक्यॉरिटी एनवायरनमेंट भी बदल गया। अब हम सारा बौद्धिक ढांचा बदलने की तरफ जा रहे हैं कि कैसे हम इन नए युद्धों की तकनीक समझें और कैसे इनका हल निकालें।

आज चीन ने अपने आक्रामक रवैये से शीत युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी है। ताइवान में जो हो रहा है, उस पर हलचल मची हुई है। इसे देखते हुए लगभग सारे ही देश रक्षा तकनीक और हथियारों पर बहुत ध्यान दे रहे हैं।

नए शीतयुद्ध का दौर

हर्ष वी.पंत।।

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। खासकर अगर हम हिंद–प्रशांत इलाके की बात करें, तो यहां बहुत हलचल मची हुई है। चीन का आक्रामक रुख तो सब देख ही रहे हैं, साथ ही यहां पश्चिमी देश भी अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं। यहां ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान हैं, जो अपनी रणनीति में बदलाव ला रहे हैं। इसे देखते हुए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के ढांचे में भी बड़ी तेजी से बदलाव आ रहे हैं। परंपरागत हथियारों की जो होड़ होती है, उसमें अंदरूनी राजनीति अंतरराष्ट्रीय राजनीति से काफी–कुछ जुड़ी हुई होती है।

आज चीन ने अपने आक्रामक रवैये से शीत युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी है। ताइवान में जो हो रहा है, उस पर हलचल मची हुई है। इसे देखते हुए लगभग सारे ही देश रक्षा तकनीक और हथियारों पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। ऑकस डील को ही देखें तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी की डील की है। भारत ने भी काफी रक्षा खरीद करने की कोशिश की है। इसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में और द्विध्रुवीय सहभागिता में हथियारों की तकनीक बड़ा मुद्दा बन गई है।

इसमें भारत जापान, रूस, अमेरिका और फ्रांस के साथ समझौते कर रहा है। भारत की सेना भी

चाहेगी कि उसके पास नई तकनीक हो। चीन या पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें करते हैं, और जिस तरह से इन दोनों देशों की सीमाओं पर सेनाएं आमने–सामने हैं, उसे देखते हुए भारत के लिए यह स्वाभाविक है कि वह रक्षा तकनीक पर फोकस करे। भारत अपनी पॉलिसी उस तरफ ले जाएगा, जहां वह रक्षा तकनीक खुद भी बना सके और दूसरों से भी खरीद सके।

मगर जब लंबी दूरी के इंगेजमेंट की बात करें तो आज तकनीक इस स्तर पर पहुंच चुकी है, जब हम पुराने दायरे से चीजों को नहीं देख सकते। जिस तरह की टकराव भरी स्थिति की संभावना व्यक्त की जा रही है, वह परंपरागत टकराव की तरह नहीं है कि आमने–सामने दो सेनाएं खड़ी हुई हैं और एक–दूसरे को निशाना बना रही हैं। अब युद्ध क्षेत्र अब बदल गया है। अब तो जो अर्थव्यवस्था है, वह भी युद्ध क्षेत्र है। उसमें परंपरागत रक्षा तकनीक पर तो फोकस है ही, लेकिन साइबर तकनीक और जगह–जगह अपने अड्डे बनाने जैसे गैर परंपरागत उपायों पर भी फोकस हो रहा है। अड्डे की बात करें तो चीन ने भारत के आसपास कई जगह अपने पोर्ट बना लिए हैं। इससे वह भारत को भी कंट्रोल कर सकता है, दूसरी तरफ अपनी ताकत भी बढ़ा सकता है। ऐसे ही भारत भी अपने अलग–अलग पोर्ट बना रहा है। मॉरीशस और अन्य द्वीपों की बात होती है, जहां से कि भारत उपयुक्त प्रतिक्रिया दे सकता है। ऐसे ही अमेरिका की कोशिश है कि अफगानिस्तान से निकलने के बाद भी वह नजर बनाए रखे। सैटलाइट तो होते ही हैं, लेकिन उसे जमीन भी चाहिए। बात ड्रोन की ही करें, तो ड्रोन का अटैक क्षेत्र सीमित है। अमेरिका भले अपने कमांड सेंटर में बैठकर ड्रोन ऑपरेट कर ले, लेकिन ड्रोन को उड़ाने के लिए एक बेस चाहिए होता है। इसी तरह भारत–पाक सीमा पर पाकिस्तान बहुत सारे ड्रोन का प्रयोग कर रहा है, तो भारत के सामने चुनौती है कि कैसे वह उसे बंद करे। ऐसे में परंपरागत चीजें उतनी काम नहीं आने की। तकनीक के विकास के साथ युद्ध पर लगे राजनीतिक प्रतिबंध बताते हैं कि अब शीतयुद्ध वाला समय नहीं रहा।

अष्टयोग-5083

4	1			2		3
	35	6	30	1	32	7
7	5		3		4	
	29	2	31	4	31	
2	4				6	
	29		40	5	34	6
5	1	3		7		

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों ओर के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5082 का हल

7	6	5	4	3	2	1
2	39	1	29	6	26	5
5	6	7	1	2	3	4
4	30	2	25	1	34	6
1	2	3	4	5	6	7
6	30	6	39	4	35	3
3	5	4	6	7	1	2

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

एक-दूसरे को लिमिटेड नुकसान पहुंचा सके

मोहन। आज अगर अमेरिका और चीन शीतयुद्ध की ओर जा रहे हैं तो यह ऐसा युद्ध होगा, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के व्यापारिक साझेदार तो रहेंगे ही, साथ ही यह भी नहीं चाहेंगे कि दोनों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचे। ऐसे में किस तरह से आप यह युद्ध लड़ें कि एक–दूसरे को लिमिटेड नुकसान पहुंचा सकें, इसी पर सोचा जा रहा है।

इसका एक कोण सैन्य गतिविधियां हैं तो दूसरा है चीन और रूस का नया तरीका। ये दोनों अब साइबर अटैक कर रहे हैं। इसमें इन पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता क्योंकि इसमें जल्दी सबूत नहीं मिलते। अगर मिलते भी हैं तो अगला कह देता है कि इसमें उसका कोई रोल नहीं है क्योंकि इंटरनेट का कोई भी प्रयोग कर सकता है। इसका रूस और चीन बहुत फायदा उठा रहे हैं। वे यूरोप, अमेरिका, भारत और पश्चिमी देशों के खुले लोकतांत्रिक समाजों पर अटैक कर रहे हैं। भारत में भी मुंबई पावर फेलियर के पीछे चीन के साइबर अटैक की चर्चा हुई थी। इसे रोकने या कम करने के लिए हम यह दिखा सकते हैं कि हमारे पास भी साइबर अटैक की क्षमता है और हम अटैक भी कर सकते हैं।